उस आधार पर आरक्षण आरक्षण क्योंकि यह किसी का नहीं है

यह दावा करने के लिए कि एक विशेष खेल को शामिल किया जाए

प्रॉस्पेक्टस में प्रदान की गई सूची। यह विभाग के लिए है

खेलों की ऐसी सूची प्रदान करने के लिए चिंतित हैं। "

सीखा न्यायाधीश द्वारा यह भी देखा गया कि मुक्केबाजी के खेल को छोड़कर वैध कारण भी दिए गए थे। जैसा कि मेरे ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आने वाले सभी समयों के लिए एक विशेष खेल जारी रखना चाहिए और शूटिंग के खेल को बाहर करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वैध कारण दिए गए हैं।

(५) मुझे याचिकाकर्ता के लिए सीखे हुए वकील के विवाद में कोई बल भी नहीं मिला है कि खेल के विभिन्न विषयों में पिछले तीन वर्षों की उपलब्धि के बाद से कम से कम तीन साल का नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष खिलाड़ी शिफ्ट करना चाहता था, तो वह किसी अन्य खेल में स्थानांतरित हो सकता है। प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, तीन साल के प्राप्त होने वाले माता-पिता को केवल प्रॉस्पेक्टस में वर्णित खेलों में ध्यान में रखा जाना चाहिए, एक बार यह आयोजित किया जाता है कि एक विशेष खेल को वैध कारणों से बाहर रखा जा सकता है, खिलाड़ी को दिए जा रहे किसी भी नोटिस का प्रश्न किसी भी गिनती पर नहीं उठता है, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के साथ यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एक बार एक खेल शामिल है। इसे बाहर नहीं किया जा सकता है।

(६) पूर्वगामी कारणों के लिए। मुझे इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। जो इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

जज जवाहर लाल गुप्ता

कीर्ति पार्शद जैन और अन्य- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य-उत्तरदाताओं

1901 का सिविल रिट याचिका संख्या 734।

1 अप्रैल, 1991

हेल्ड, कि यह अधिकारियों को अपनी रसीद के 60 दिनों के भीतर इस्तीफे की स्वीकृति को सूचित करने के लिए अवलंबी है। अभिव्यक्ति का उपयोग "अधिक नहीं" संकेत देता है कि अधिकारियों के लिए स्वीकृति को सूचित करना अनिवार्य है। इस तरह के एक नोटिफि-केशन के बिना, इस्तीफा प्रभावी नहीं होता है। इस प्रावधान का कारण यह है कि एक नगरपालिका समिति का एक सदस्य एक निर्वाचित कार्यालय रखता है और वैधानिक कर्तव्यों का बोझ होता है जिसमें काफी सार्वजनिक हित शामिल होता है। यह केवल अधिसूचना के प्रकाशन पर है कि "सदस्य को अपनी सीट खाली करने के लिए समझा जाएगा"। एस। 13 किसी सदस्य को 15 दिनों के भीतर इस्तीफा वापस लेने का अधिकार देता है, भले ही उसे इससे पहले स्वीकार कर लिया गया हो। वहाँ- के बाद, यदि स्वीकृति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है, तो सदस्य को इसे वापस लेने का अधिकार है। एकमात्र अंतर यह होगा कि यह प्राधिकरण के लिए विवेकाधीन होगा कि वे वापसी की अनुमति दें या इसे अस्वीकार करें। (पारस 9. 10. 11)

आयोजित, जहां आधिकारिक गजट में स्वीकृति के प्रकाशन से पहले निकासी के लिए आवेदन किया गया था, उपायुक्त को वापसी की अनुमति देने का विवेक था। उन्होंने ऐसा करते समय अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया। नतीजतन एस। 13. के प्रावधानों के उल्लंघन में लगाए गए आदेश को पारित नहीं किया गया था (पैरा 12)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि यह माननीय अदालत मामले के रिकॉर्ड को बुलाने और उसी के

एक अपमान के बाद प्रसन्न हो सकती है।

(ए) सर्टिफिकेट की प्रकृति में एक रिट जारी करें, उत्तरदाताओं द्वारा पारित किए गए आदेश (अनुलग्नक पी -4) को समाप्त करना।

(बी) मंडमस की प्रकृति में रिट जारी करना, आधिकारिक राजपत्र में रिससॉन डेंट्स नंबर ३ से ६ के इस्तीफे को सूचित करने के लिए res- पॉन्डेंट्स १ और २ को निर्देशित करना:

(ग) किसी भी अन्य रिट, ऑर्डर या दिशा को जारी करें जो यह माननीय अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत फिट हो सकता है।

अपीलकर्ताओं के लिए सत्य पाल जैन, अधिवक्ता। आर। पी। सिंह। उत्तरदाताओं के लिए वकील। 3. 4 से 6।

प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए जसवंत Phrgat A.A.G.

प्रलय

जज जे. एल. गुप्ता,

(1) याचिकाकर्ता जो नगरपालिका समिति, अंबाला सिटी के नगरपालिका आयुक्त हैं, ने 3 जनवरी, 1991 के आदेश को डिप्टी कमिश्नर, अंबाला (एनेक्स्योर पी -4) द्वारा पारित किया है। इस आदेश के अनुसार, 2 अक्टूबर, 1990 को चार नगरपालिका आयुक्तों (उत्तरदाताओं के उत्तरदाताओं नं। 3 से 6) द्वारा प्रस्तुत किए गए इस्तीफे को, जिसे उसी दिन उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया था, को वापस ले जाने की अनुमति दी गई थी और यह घोषित किया गया था कि उन्हें घोषित किया जाना चाहिए नगरपालिका समिति, अंबाला सिटी के सदस्यों के रूप में जारी रखने के लिए माना जाता है।

(२) सबसे पहले, घटनाओं का अनुक्रम। उत्तरदाताओं ने 3 से 6 के साथ

एक अन्य व्यक्ति के साथ 2 अक्टूबर, 1990 को डिप्टी कमिश्नर, अंबाला को इस्तीफा दे दिया, एनेक्स्योर आर -1 में लेटर। ऐसा प्रतीत होता है कि उसी दिन उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके बाद, 22 नवंबर, 1990 को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को सूचित करते हुए एक और पत्र प्रस्तुत किया कि वे अपने इस्तीफे को नहीं दबा रहे थे। 28 नवंबर, 1990 को डिप्टी कमिश्नर ने निदेशक, स्थानीय निकायों, हरियाणा को सूचित किया- चार व्यक्तियों के अनुरोध को उनके पुनर्विचार-राष्ट्र की वापसी के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र द्वारा जो कि एनेक्स्योर पी -3 में है, डिप्टी कमिश्नर ने निदेशक, स्थानीय निकायों से स्पष्टीकरण मांगा। इस मामले को कानूनी याद करने वाले को भी संदर्भित किया गया है और अंत में, आदेश दिया गया आदेश दिया गया है, उपायुक्त ने चार रेस-पॉन्डेंट्स के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और घोषणा की है कि उन्हें नगरपालिका आयुक्तों को जारी रखने के लिए समझा जाएगा।

(३) रिट याचिका के नोटिस के जवाब में, दो लिखित राज्य-माता-पिता दायर किए गए हैं। उत्तरदाताओं की ओर से नं। 1 और 2 उत्तर डिप्टी कमिश्नर, अंबाला द्वारा दायर किए गए हैं, जबकि रिस्पॉन्स-डेंट नं। 3 से 6 ने एक अलग लिखित बयान दायर किया है। रिट याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी के लिए एक चुनौती सहित विभिन्न प्रारंभिक आपत्तियों को बढ़ाने के अलावा, यह औसत है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम के सेक्टन 13 के प्रावधानों के मद्देनजर, एक सदस्य को एक सीट खाली नहीं माना जा सकता है यदि अधिसूचना के बारे में अधिसूचना के बारे में अधिसूचना के बारे में एक सीट को खाली कर दिया जाए। उनके इस्तीफे की स्वीकृति 60 दिनों की अवधि के भीतर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होती है। यह भी सुझाव दिया गया है कि इस्तीफा सरकार द्वारा अंत में स्वीकार किया जा सकता है और उपायुक्त द्वारा नहीं। उत्तरदाताओं ने 3 से 6 को यह भी माना है कि इस्तीफे की स्वीकृति कभी भी उनके लिए नहीं थी। रिट याचिका में विभिन्न अन्य औसत भी विरोधाभास किए गए हैं। उनके लिखित बयानों में res- तालाबों द्वारा उठाए गए अन्य विवाद वर्तमान विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

(4) श्री एस.पी. जैन, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि उत्तरदाताओं संख्या 3 से 6 द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा 2 अक्टूबर 1990 को उप आयुक्त द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। इस्तीफा स्वीकार होने से प्रतिवादी नगर निगम आयुक्त नहीं रहे। फिर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन केवल प्रक्रियात्मक/मंत्रिस्तरीय अधिनियम था जो उनके इस्तीफे की स्वीकृति का प्रभाव इसे दूर भी नहीं ले जा सकता।

(५) उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान याचिका को बनाए रखने के लिए कोई लोकल स्टैंडी नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कि इस्तीफे की स्वीकृति को संबंधित व्यक्तियों को विधिवत रूप से सूचित नहीं किया जाता है, तब तक यह पूरी तरह से अप्रभावी था और इस मामले में इस तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं जो अदालत द्वारा अपने रिट जुरिसडिक-टियोन के अभ्यास में नहीं जा सकते थे ।

(६) विवाद हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, १ ९। ३ की धारा १३ में निहित प्रावधान पर टिका है। यह अंडर के रूप में पढ़ता है:

"13. यदि कोई समिति का कोई सदस्य अपने कार्यालय से इस्तीफा देने की इच्छा रखता है, तो वह उपायुक्त को लिखित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है, डिप्टी कॉमिस द्वारा उक्त सदस्य के आवेदन की प्राप्ति के बाद साठ दिनों से अधिक समय बाद नहीं, जिसमें सदस्य को अपनी सीट खाली करने के लिए समझा जाएगा;

बशर्ते कि यदि कोई सदस्य जिसने इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो वह इस्तीफा देने के लिए डिप्टी कमिश्नर द्वारा रसीद के पंद्रह दिनों के भीतर डिप्टी कमिश्नर के पास आवेदन कर सकता है, और इस्तीफा देने के लिए आवेदन किया जाएगा। वापस ले लिया गया है। "

(7) जैसा कि १ इस प्रावधान को पढ़ना है, यह एक सदस्य को उपायुक्त द्वारा अपनी रसीद के १५ दिनों के भीतर अपना इस्तीफा वापस लेने का पूर्ण अधिकार देता है। तुरंत, वापसी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर, इस्तीफे को "बिना कुछ के" वापस ले जाने के लिए समझा जाता है। इसके अलावा, इस्तीफा-टियोन की स्वीकृति को डिप्टी कमिश्नर द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अधिसूचित किया जाना चाहिए। । यह केवल अधिसूचना के सार्वजनिक रूप से है कि "सदस्य को अपनी सीट खाली करने के लिए समझा जाएगा"।

(8) मैं याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील की याचिका को बनाए रखने में असमर्थ हूं कि डिप्टी कमिश्नर ने २ अक्टूबर, १ ९९ ० को खुद को स्वीकार कर

लिया है, उत्तरदाताओं ने ३ से ६ से ६ से ६ से ६ से ६ को जारी रखने के हकदार नहीं थे। धारा 13 के प्रावधानों के तहत स्वीकृति 15 दिनों की अवधि के लिए इब्तिदाई है जैसा कि प्रोविसो में धारा 13 में उल्लेख किया गया है। उस अवधि के दौरान यह इस्तीफा वापस लेने के लिए सदस्य के लिए खुला है और उपायुक्त से आदेश के बिना, वापसी बन जाती है स्वचालित रूप से परिणामस्वरूप, यह तर्क देना गलत है कि इस्तीफे की स्वीकृति 2 अक्टूबर, 1990 को ही पूर्ण और प्रभावी थी।

(९) जो अगला सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उत्तरदाताओं के उत्तरदाताओं के पास नहीं है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर अनिवार्य रूप से मूल प्रावधान की व्याख्या पर निर्भर करेगा। यह प्रदान करता है कि इस्तीफे की स्वीकृति "आधिकारिक राजपत्र में 15 दिनों से कम नहीं और रसीद के 60 दिनों से अधिक नहीं की तारीख पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ....."। मेरे विचार में अधिकारियों पर अपनी रसीद के 60 दिनों के भीतर इस्तीफे की स्वीकृति को सूचित करना अवलंबी है। अभिव्यक्ति का उपयोग "अधिक नहीं" Indi-cation देता है कि अधिकारियों के लिए स्वीकृति को सूचित करना अनिवार्य है। इस तरह की अधिसूचना के बिना, इस्तीफा प्रभावी नहीं होता है।

(१०) इस प्रावधान को बनाने का कारण यह है कि एक नगरपालिका समिति का एक सदस्य एक निर्वाचित कार्यालय रखता है और वैधानिक कर्तव्यों का बोझ होता है जिसमें काफी सार्वजनिक हित शामिल होता है। विधानमंडल ने अपने ज्ञान में 15 दिनों के भीतर इस्तीफे को वापस लेने के लिए सदस्य को एक विकल्प देने के लिए चुना है और यह भी कि 60 दिनों के भीतर स्वीकृति को सूचित करने के लिए अधिकारियों पर यह भी ध्यान दिया गया है। यह केवल अधिसूचना के प्रकाशन पर है कि "सदस्य को अपनी सीट खाली करने के लिए समझा जाएगा।"

(११) क्या किसी सदस्य के लिए किसी भी समय इस्तीफा वापस लेना संभव है, किसी भी समय इसकी स्वीकृति आधिकारिक गेज़ाइट में नोटिस की गई है? हाँ मुझे लगता है। धारा 13, मेरे विचार में, एक सदस्य को 15 दिनों के भीतर इस्तीफा वापस लेने के लिए एक रिगेट देता है, भले ही उसे इससे पहले स्वीकार कर लिया गया हो। इसके बाद, यह स्वीकृति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित

नहीं की गई है, सदस्य को इसे वापस लेने का अधिकार है। एकमात्र अंतर यह होगा कि यह प्राधिकरण के लिए विवेकाधीन होगा कि वे वापसी की अनुमति दें या इसे अस्वीकार करें।

(१२) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वापसी के लिए आवेदन २२ नवंबर, १ ९९ ० को किया गया था। यह आधिकारिक राजपत्र में स्वीकृति के पब्लिक-टियोन से पहले था। मुझे लगता है, डिप्टी कमिश्नर के पास वापसी की अनुमति देने का विवेक था। वह ऐसा करते समय अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। नतीजतन, धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन में लगाए गए आदेश (अनुलग्नक पी -4) को पारित नहीं किया गया था।

(१३) मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए कंटेंट में जाना आवश्यक है- याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडी, आदि के बारे में।

(१४) रिट याचिका इस प्रकार विफल हो जाती है और लागत के साथ खारिज कर दी जाती है। वकील का शुल्क रु। 1,000।

आर.एन.आर.

जज एन। के। सोढी

DOABA सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, नवंशहर, पंजाब, याचिकाकर्ता।

बनाम

जैस्मिंदर सिंह और एक अन्य, -सोन्सेंटेंट्स।

1987 के सिविल रिट याचिका नंबर 85/7।

23 अप्रैल, 1991।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-एस। 25-सेवाओं की समाप्ति- काम करने वाला भी, भले ही प्रोबेशनर माना जाता है कि एस। 25F का अनुपालन करने के लिए प्रबंधन के लिए 18 महीने की सेवा-अनिवार्य में डाल दिया गया था-

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
जींद, हरियाणा